खाकी

कानून से बेपरवाह मुंबई के 'कमाऊ पूत' और उनके आका

विकास नारायण राय

पुलिस और राजनीति में 'कमाऊ पूत' एक जमी-जमायी परंपरा है। हालाँकि यह विरल ही मिलेगा कि मुंबई पुलिस के असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाझे जैसा कोई कमाऊ पूत कानून के हाथों पकड़ा जाए। इन कमाऊ पूतों की प्रजाति में सबसे उल्लेखनीय बात होती है, इनका कानून के प्रति सम्पूर्ण तिरस्कार। ये कानून के शासन से बेपरवाह होते हैं; इनके आका ही सम्बंधित क्षेत्र में कानून लागू करने के सर्वेसर्वा जो हुए।

सचिन वाझे के माध्यम से सौ करोड़ महीना उगाही का मुंबई पुलिस प्रकरण शायद ही सामने आता अगर उद्योगपति मुकेश अंबानी के निवास पर स्कोर्पियो में धमकी के नोट के साथ जेलेटिन की छड़े मिलने और स्कोर्पियो मालिक मनसुख हिरानी की कुछ दिनों बाद हुई हत्या के मामले में उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई होती। तब से तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के आरोपों-प्रत्यारोपों के गिर्द घूमता यह मामला राजनीतिक तूल पकड़ता चला गया है। यहाँ तक कि केंद्र की मोदी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह अपनी संकट-मोचक सीबीआई समेत परमबीर भड़ाना की ओर से और महाराष्ट्र की महाअघाड़ी गठबंधन सरकार के मुख्य किरदार शरद पवार, अनिल देशमुख की ओर से एक छाया युद्ध का मोर्चा गर्म किये हुए हैं।

जहाँ वाझे की 'कमाऊ पूत' भूमिका में शक नहीं और स्वयं देशमुख शक के दायरे में हैं, क्या इन दोनों के आका भी बेचैन नहीं होंगे? मामला फिलहाल मुंबई उच्च न्यायालय के सामने जरूर है, लेकिन इसमें राजनीति का दखल कदम-कदम पर देखा जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश से जांच की घोषणा शायद ही किसी का विश्वास अर्जित कर सके। वाझे की भी किस्मत राजनीतिक समीकरण बदलने से पलटा खा सकती है और वह बेदाग बरी भी हो सकता है।

लेकिन सभी कमाऊ पूत इतनी किस्मत वाले नहीं होते। दरअसल, आज देश में कम ही पुलिस यूनिट मिलेंगी जहाँ कमाऊ पूत न पाले जाते हों। राजनीति में इन्हें फण्ड रेजर कहते हैं, जबकि पुलिस में यह सुविधा नहीं होती। हाल में हरियाणा के गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरेट में राज्य विजिलेंस ब्यूरो ने ऐसे ही एक थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर और उसके सहयोगी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध चार्जशीट अदालत में दी है। दो व्यापारियों के व्यवसायिक विवाद में जिसका क्षेत्र करनाल/दिल्ली था, एक व्यापारी को गुरुग्राम की इस कमाऊ पूत पुलिस टीम ने अगवा कर लिया। उसे गैर कानूनी हिरासत और यातना से 57 लाख रुपये देकर ही छुट्टी मिल सकी।

दशकों से हरियाणा में चलन रहा है कि थानाध्यक्ष स्थानीय प्रभावशाली राजनेताओं की सिफारिश पर लगाये जाते हैं, बेशक उनके तबादलों/नियुक्तियों के आदेश पर किसी न किसी पुलिस अधिकारी के दस्तखत क्यों न

सचिन वाझे की 'कमाऊ पूत' भूमिका में शक नहीं

हों। इसमें पैसे का लेन-देन भी छिपा नहीं होता। लेकिन, उपरोक्त गुरुग्राम मामले में भी, कानून का कभी-कभार गिरने वाला नजला बस कमाऊ पूत तक सीमित रहा और आका को नहीं छू सका। समझ यह कि बाद में आका के सहयोग से कमाऊ पूत को भी बचा लिया जाएगा। कभी एक फर्जी एनकाउंटर में पकड़ा गया सचिन वाझे भी ठीक इसी तरह मुंबई पुलिस में फल-फूल रहा था। परमबीर सिंह की मानें तो उनके मातहत इन्स्पेक्टर (सचिन वाझे) को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई के ठिकानों से अपने लिए 100 करोड़ प्रतिमाह वसूली करने का लक्ष्य दिया था। सवाल है कि राज्य का गृह मंत्री एक इन्स्पेक्टर रैंक के जूनियर पुलिसकर्मी को इतनी बड़ी रकम जुटाने का जिम्मा देने की कैसे सोच भी सकता था, जब तक कि उसे पक्का पता न हो कि इस तरह के कार्यकलाप में वाझे और पुलिस कमिश्नर का रिश्ता बेहद प्रगाढ़ है। ध्यान रहे, परमबीर सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश पर ही वाझे को 16 वर्ष बाद पुलिस विभाग में पुन: बहाली मिली थी।

मुंबई उच्च न्यायालय ने भी सवाल खड़ा किया है कि वझे से सब कुछ जानने के बाद भी परमबीर खामोश क्यों बने रहे? उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? लेकिन सीबीआई द्वारा जेलेटिन मामले में वझे की गिरफ्तारी के बाद, बेशक अपनी चमड़ी बचाने के लिए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में परमबीर ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री (अजित पवार, शरद पवार के भतीजे) को देशमुख की 100 करोड़ की मांग से तभी परिचित करा दिया था। दोनों ने ही इसका खंडन नहीं किया है। सवाल है, देशमुख के पीछे किस आका का वरदहस्त था कि उद्धव और अजित पवार खामोश बने रहे थे।

ऐसे में, मुंबई पुलिस के इस अभूतपूर्व शर्मनाक पुलिस प्रकरण को सामान्य पुलिस सुधार या वझे जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के संहार के रूटीन नैतिक चश्मे से देखना बेमानी होगा। यह पुलिस द्वारा कानून के सम्पूर्ण तिरस्कार का व्यापक मसला है, जिसमें उसे राजनीतिक सत्ताधारी का प्रेरक वरदहस्त प्राप्त है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय में अमित शाह के काबिज होने के बाद यह सिलसिला उत्तरोत्तर बढ़-चढ़ कर हावी होता जा रहा है।

(पूर्व डायरेक्टर, नेशनल पुलिस अकादमी, हैदराबाद)

हड़ताल अपनी जगह, पर दिल में मोदी जी हैं, और दिल है कि मानता नहीं- बैंककर्मी

विवेक

जय सिंह : "शरद जी गुडमॉर्निंग, उठ गए हों, तो अब जाग भी जाइए", सोचो बैंक वाले दो दिन से कितना प्रतीकात्मक विरोध कर रहे थे, सच में विरोध करते तो न ये बेरोजगारी बढ़ रही होती न आपका बैंक प्राइवेट होता।

शरदकांत: बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा विषय है और निजीकरण पर लंबी तार्किक बहस हो सकती है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं लेकिन मोदी जी हमारे दिल में बसते हैं और दिल है कि मानता नहीं।

शरदकान्त विनोद और जय सिंह दोनों बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर पद पर तैनात हैं। बीती 15-16 मार्च को देश भर के सरकारी बैंक कर्मचारी, बैंकों के निजीकरण के खिलाफ सड़कों पर उतरे, पर सरकार पर उसका कोई असर नहीं हुआ7 क्या इस बात का अंदाजा बैंक यूनियनों को नहीं रहा होगा कि सरकार पर इसका कोई असर नहीं होने वाला7 इस बात का जवाब जय सिंह के वाक्य में ही छिपा हुआ है।

देश भर में आंदोलनों और सरकार के खिलाफ एक व्यापक अविश्वास का माहौल बना हुआ है, इन सबके बावजूद सरकार के माथे पर सलबटें पड़ने से उलट खुद प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर आंदोलनकारियों को परजीवी होने के साथ-साथ अब सिविल सेवा के अधिकारियों पर भी तंज कसते देखे जा रहे हैं। एक लोकतान्त्रिक व्यवस्था में इतना दुस्साहस कर पाने की क्षमता दैवीय माध्यम से नहीं अपितु उस देश की जनता के माध्यम से ही मिलती है जिसका जीता जागता उदाहरण बैंक ऑफ इंडिया के शरदकान्त विनोद देखे जा सकते हैं।

बैंक कर्मियों की हड़ताल में शामिल अच्छे-खासे अनुपात में बैंक कर्मी अपनी मांगों को लेकर खुद ही या तो सहमत नहीं या शशांकित है। इसी प्रकार एक बड़ा अनुपात बैंकों का निजीकरण किये जाने के पक्ष में है और नरेन्द्र मोदी के इस कदम को एक बेहतर सुधार के रूप में देखता है। अब जब बैंक के भीतर से सरकार के पक्ष में आवाज आएगी तो बाकी जनता बैंक कर्मचारियों के लिए मशालें कैसे उठा लेगी।

बैंक ऑफ इंडिया के उच्च पद पर आसीन संध्या (बदला हुआ नाम) को कहीं से भनग लगी है कि उनके बैंक को टीसीएस खरीदेगी। इस बात को लेकर वह उत्साहित है क्योंकि वह मानती हैं कि उन जैसे कर्मठ महिला की कद्र टाटा जैसी कंपनी ही कर सकती है जो अपने कर्मचारी का सम्मान करना जानती हो। पर क्या उनके बैंक को मुकेश अंबानी खरीद लें तब भी वह इतना ही उत्साहित हैं? संध्या ने कहा इसी बात के डर से तो हम आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यानि, यदि टाटा के पास जाएँ तो खुशी है पर रिलायन्स के पास जाना पड़ गया तो आत्महत्या जैसा है।

समझा जा सकता है कि सरकार की अनदेखी के बावजूद कर्मचारी किसी खराब एचआर पॉलिसी वाली कंपनी के तहत नहीं जाना चाहते। अब इतनी धुंध में होने वाले आंदोलनों को स्पष्टता से देख पाना मुश्किल है पर एक मटमैला अक्स जय सिंह और शरद कान्त विनोद की बातचीत में देखा जा सकता है।

जनमानस को बेशक न याद हो पर बैंक कर्मियों को जरूर याद होगा कि जिस नोटबंदी का पहले दिन से फेल होना सुनिश्चित था उसके असफल होने का ठीकरा 50 दिन बाद बैंक कर्मियों पर फोड़ा गया और आमजन ने इसपर यकीन भी किया। ठीक इसी प्रकार जब बैंक कर्मियों ने हड़ताल की तो उन्हे कामचोर बताने का प्रचार सरकार समर्थित आईटी सेल ने धूमधाम से करके माहौल अपने पक्ष में रखा, जबकि बैंक कर्मी अकेले ऐसे जीव हैं जिनको हड़ताल के बाद अपनी तनख्वाह भी कटवानी पड़ती है और उस दिन का बचा काम अगले दिन करना भी पड़ता है। बावजूद इसके आम जन इन्हे

कामचोर मानते हैं, कमाल की बात है कि खुद कई बैंक कर्मी भी आईटी सेल के कार्यकर्ता के रूप में जाने अनजाने अपने घर के दरवाजे उखाड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अनुपपुर जिले में पोस्टिंग पाए एसपी राजेश पांडे खुद को फ्रन्ट लाइन कोरोना वॉरियर मानते हैं और बैंक कर्मियों को कामचोर। उनके साथ काम करने वाले सभी का मत है कि एसपी साहब खुद हर हफ्ते बस पार्टियां करते हैं और सरकारी खर्चे पर घूमते हैं। भाजपा की जिला अध्यक्ष से राखी बँधवा जन्मदिन के केक कटवाते हैं और खुद को सबसे कर्मठ का तमगा देते हैं। जबकि जो लोग भी लॉकडाउन पीरियड में घर से बाहर निकले होंगे उन्हे पता होगा कि पुलिस ने उनकी किस तरह मदद की थी और एक बैंक कर्मी ने किस तरह।

लॉक डाउन के दौरान सरकारी बैंक कर्मचारी अपने रिस्क पर घर से किसी तरह बैंक आता रहा और पब्लिक डीलिंग भी करता रहा। इन सबके बीच दिल्ली जैसे शहर में मेट्रो कोरोना वॉरियर के लिए चलाई गई पर बैंकर को न मेट्रो में चढ़ने दिया गया न ही आज तक कभी प्रधानमंत्री ने इनका आभार ही प्रकट किया, जबकि, सरकार के पाप के जहर को इन्ही नीलकंठों ने साधा है।

अब सवाल है कि इतना सब हो कैसे जाता है और शरद कान्त विनोद जैसे लोग खुद के नुकसान से ही अपनी आंखे कैसे मूँदे रहते है? तो आपने गौर किया होगा कि पिछले दो तीन दिन से अखबार में रोज ये छप रहा है कि अगले 9 दिन में बैंक 6 दिन बंद होंगे, अपने-अपने काम निबटा लीजिए। इसको पढ़ने के बाद आम-जन में यह बात पक्के तौर पर मान ली गई है कि ये तो बस बैंककर्मी छुट्टी लेते रहते हैं। जबकि किसी भी अन्य विभाग में भी इतनी ही छुट्टी सरकार द्वारा दी जा रही है पर खबर केवल बैंक को लेकर छपेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि माहौल को सरकार के पक्ष में बनाने का जिम्मा भी अखबार को मिला हुआ है। एक सहकर्मी ने बताया कि शरद कान्त जैसे नागरिक देश के वफादार होने का दावा सिर्फ अपनी हिन्दू-मुस्लिम राजनीति से तय करते हैं जबकि सच्चाई है कि ऐसे लोग अपनी संस्था के ही वफादार नहीं। इसी कारण ये एकदम अंधे हो चुके हैं।

जनसत्ता अखबार के हवाले से माने तो संसदीय स्थायी समिति ने सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट 'भारत नेट परियोजना' की विफलता का ठीकरा बीएसएनअल, पॉवर ग्रिड और रेलटेल के सिर फोड़ते हुए कहा कि ये दोनों कंपनियां एकदम निकम्मी हैं और शायद निजी कंपनी इस काम को बेहतर ढंग से पूरा करती। समिति ने यह भी कहा कि जिस तरह से सरकारी कंपनियों ने काम किया उससे पता चलता है कि उनके पास योग्यता और संसाधनो का अभाव था। इस प्रकार के प्रचार से जनता का दिमाग सरकारी कंपनियों के लिए जहर से भर दिया जाएगा और बाद में निजी कंपनियों को काम देने के फैसले का स्वागत यही जनता करेगी। जबकि रिपोर्ट में दो शब्द साफ लिखे हैं "योग्यता" और "संसाधन", तो योग्यता और संसाधन दोनों मुहैया करवाना सरकार का काम है जबकि सच यह है कि इन कंपनियों में छटनी ही हुई है न की नई भर्तियाँ। इस हिसाब से भारतनेट परियोजना खुद सरकार की ही विफलता है।

इसी प्रकार सरकारी बैंकों की तुलना निजी बैंकों से करते हुए उनका मनोबल तोड़ा जाता है। जबकि सरकारी बैंक रेहड़ी पटरी वालों को उतना लोन देते हैं जितना न्यूनतम बैलेन्स निजी बैंक के खाताधारक के खाते में होना चाहिए। ऐसे में प्रतिस्पर्धा के स्तर पर किसी को निकम्मा बताना नाजायज है जबकि प्रतिस्पर्धा में जिन कसौटियों पर सरकारी बैंक काम करते हैं उनको शामिल ही नहीं किया जाता। किस निजी बैंक के मैनेजर के कमरे में एक फटी लूँगी पहले आदमी खड़ा हो सकता है? किस निजी बैंक ने जनधन खाते खोल कर मोदी जी के सपनों को पूरा किया?

मोदी सरकार की हर मामले में तकरीबन एक ही रणनीति है, चरित्र हनन और फिर उसको भुनाना। कन्हैया कुमार से लेकर दिशा रवि तक और भारतीय रेल से लेकर बैंकों तक सबका चरित्र हनन और फिर उन्हे बेचना। चक्रवर्ती समिति से लेकर, नरसिंहम, जालान और नचिकेत मोर समितियों ने बैंकिंग क्षेत्र में बेहतरी के सुझाव पेश किये। मोदी सरकार ने कोई नया बहाना नहीं जोड़ा कि वो बैंक क्यू बेच रही है और इसे निजीकरण कहना भी सरासर गलत होगा। यह तो सिर्फ और सिर्फ अपने खर्च चलाने के लिए सरकार अपने बैंक बेच रही है। और यदि बैंक कर्मियों को अपना भविष्य बचाना है तो कम से कम उस बच्चे की तरह बर्ताव करना बंद करना होगा जिसके लिए घर में तो पृथ्वी शेष नाग के फन पर टिकी है और स्कूल में गुरुत्वाकर्षण के कारण।

गतांक की चीर-फ़ाड़

रजिस्ट्रार सोसाइटीज का गोरखधंधा

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 28 मार्च-3 अप्रैल 2021 के अंक में समसामयिक महत्वपूर्ण विषयों पर अनेक समाचार व लेख प्रकाशित हुए हैं। ओजोन पार्क सोसायटी की रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडबल्यूए) की चुनी हुई प्रबंध समिति को रजिस्ट्रार सोसाइटीज फ़रीदाबाद द्वारा गैर-कानूनी ढंग से बरखास्त कर एक एड हॉक कमेटी गठित करने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाने के बावजूद सेवानिवृत तत्कालीन अनिल चौधरी ने आरडब्ल्यूए का प्रशासक नियुक्त होने पर उन्हीं लोगों को तदर्थ समिति का सदस्य बना लिया, जिन पर अदालत ने रोक लगाई थी। 'ओजोन पार्क सोसाइटी को बरखास्त कर फंड लूटने का इंतजाम रिटायर होने से पहले कर गया पूर्व रजिस्ट्रार-अनिल चौधरी और उसके गुर्गों के खिलाफ़ हरियाणा विजिलेंस के पास पहुंची शिकायत' में तत्कालीन रजिस्टार व प्रशासक अनिल चौधरी द्वारा रजिस्टार सोसाइटीज विभाग की सांठ-गांठ तथा उनके चहेतों की सहायता से की जा रही सोसाइटी की बदहाली और फंड के लूट आरोपों का कच्चा चिट्ठा खोला गया है।

ध्यान रहे कि सोसाइटी की प्रबंध समिति को भंग कर तदर्थ समिति नियुक्त करने जैसा कठोर कदम तभी उठाया जाता है जब सोसाइटी के एक्ट के नियमों के उल्लंघन की घोर अनियमितताएं तथा फंड का दुरुपयोग पाया गया हो। इसके अतिरिक्त सोसाइटी के संचालन ने अनुभवी व वरिष्ठ लोगों की सहायता लेने की बजाए सोसाइटी में अपना काम-धंधा करने वाले बाहरी गैर सदस्य लोगों को एड हॉक कमेटी का सदस्य क्यों बनाया गया? स्पष्ट है कि खट्टर सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के दावे के बावजूद रजिस्ट्रार सोसाइटीज विभाग में भ्रष्ट व्यवस्था बदस्तूर कायम है।

इस दुष्प्रचार के जवाब में किसान संगठनों ने देशव्यापी ग्रामीण किसान महापंचायतें आयोजित कर जन समर्थन जुटाने का अभियान चला रखा है, जिससे इस किसान आंदोलन को मज़दूरों, व्यापारियों व अन्य वर्गों का सहयोग मिल रहा है और यह आन्दोलन एक जन आन्दोलन का रूप ले चुका है। किसान संगठनों ने आन्दोलनकारी किसानों की खेती का काम करने के लिये गांव-गांव में कमेटी बना कर किसानों की मांगे नहीं माने जाने तक दिल्ली बार्डर पर डटे रहने का संकल्प लेने के साथ ही 26 मार्च को भारत बंद करने का आह्वान किया, जिसका 'बात तो कानून वापसी के बाद ही बनेगी: राकेश टिकैत' तथा 'किसानों के समर्थन में मज़दूरों का प्रदर्शन' में खुलासा किया गया है।

पश्चिमी यूरोपीय देशों के मज़दूरों की अपेक्षाकृत सम्पन्नता व बेहतर स्थिति से आकर्षित होकर भारत, पाकिस्तान जैसे गरीब देशों के मेहनतकश किसी भी तरीके से वहां जाकर सस्ते दाम पर मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे वहां के स्थानीय मज़दूरों को अप्रवासी मज़दूर दुश्मन नज़र आते हैं। इसके कारण वीजा के कड़े नियम लागू किये जाते हैं।

'अन्य देशों में भी श्रमिक असन्तोष पनप रहा था' में मज़दूर मोर्चा के सम्पादक सतीश कुमार द्वारा अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यूरोपीय देशों के मेहनतकशों तथा भारत, पाकिस्तान जैसे गरीब देशों के मेहनतकशों के बीच अंतर्विरोधों के समीक्षा की गई है।

ध्यान रहे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने वहां के स्थानीय लोगों के हितों की सुरक्षा के लिये गैर अमेरिकी लोगों के वीजा पर कड़े प्रतिबंध लागू किए थे, जिनमें अब वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा ढील दी जा रही है।

नव-उदारवाद व स्वायत्तता देने के नाम पर संस्थानों का कॉरपोरेटीकरण करने का समर्थक तथा जातिवाद आरक्षण का विरोधी होने के बावजूद अशोक विश्वविद्यालय के प्रख्यात बुद्धिजीवी प्रोफ़ेसर प्रताप भानू मेहता और अरविंद सुब्रह्मण्यम को प्रधानमंत्री मोदी की फ़ासिस्ट नीतियों और हिंदुत्ववादी एजेंडे के प्रखर विरोधी होने के कारण विश्वविद्यालय से त्याग प्रमाणपत्र देना पड़ा, जिसका, 'बुद्धिजीवी को मोदी विरोध और मोदी समर्थन की एक जैसी दुत्कार!' तथा 'प्रताप भानू मेहता प्रकरण: विचार को बंजर बनाते किसी विश्वविद्यालय' में सटीक विश्लेषण किया गया है। स्मरण रहे कि भाजपा की मातृ संस्था आरएसएस की स्थापना हिन्दुत्ववाद के आधार पर की गई थी, जिसकी रणनीति सदैव फ़ासीवादी रही है। आरएसएस के आधारभूत सिद्धांत व मोदी जी की कौर वैचारिक नीति की आलोचना करने वाला व्यक्ति चाहे वह मोदी जी का कितना ही वफ़ादार और प्रतिभाशाली हो, उसे सहन नहीं किया जाता और उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। दरअसल अन्य योग्यताओं के अलावा मोदी जी के प्रति अन्धभक्ति व पूर्ण समर्पण की भावना अत्यंत आवश्यक है।

मोदी सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ़ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के चलते हुए चार महीने हो गए हैं। मोदी सरकार इन कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर खरीद के लिए कानून बनाने की मांग मानने की बजाए आन्दोलन को हतोत्साहित करने में लगी हुई है। आरएसएस, मोदी सरकार, भाजपा का आईटी सेल तथा मोदी समर्थक मीडिया आन्दोलन को बदनाम करने के लिये इस नेगेटिव को मजबूत करने में लगे हुए हैं कि यह आन्दोलन किसानों का नहीं है और इसे असामाजिक, राष्ट्रद्रोही व आतंकवादी तत्व चला रहे हैं, जो सरकार व किसान संगठनों के बीच वार्ता को निष्फल करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में किसान नेताओं को सजग रहने और राजनेताओं की खिलाफत करने में संयम रखने की आवश्यकता है।